

‘गैंगस्टर्सों ते वार’ अभियान तेज:
446 ठिकानों पर छापेमारी



चंडीगढ़, 1 जून:पंजाब को अपराध और नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियानों के तहत पंजाब पुलिस ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्यभर में गैंगस्टर्सों और उनके सहयोगियों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया। ‘गैंगस्टर्सों ते वार’ अभियान के 132वें दिन पुलिस टीमों ने 446 चिन्हित स्थानों पर एक साथ छापेमारी की और 192 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

यह अभियान 20 जनवरी 2026 को पुलिस महानिदेशक गौरव यादव द्वारा शुरू किया गया था, जिसे एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) के समन्वय से राज्यभर में चलाया जा रहा है। पुलिस के अनुसार आज की कार्रवाई के दौरान एक हथियार भी बरामद किया गया। अभियान शुरू होने से अब तक कुल 33,119 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 पर गुप्त रूप से गैंगस्टर्सों, वांछित अपराधियों और अपराधिक गतिविधियों की जानकारी साझा करें।

राज्यपाल ने 16वीं पंजाब विधानसभा का 12वां सत्र किया समाप्त



चंडीगढ़, 1 जून 2026:पंजाब के राज्यपाल ने 16वीं पंजाब विधानसभा के 12वें सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त (प्रोरोग) कर दिया है। यह सत्र 1 मई 2026 को आयोजित बैठक के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था।

विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, राज्यपाल ने संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 31 मई 2026 को आदेश जारी कर विधानसभा के इस सत्र को औपचारिक रूप से उठाने की मंजूरी प्रदान की। इसके साथ ही 16वीं पंजाब विधानसभा का 12वां सत्र विधिवत रूप से समाप्त हो गया है।

उल्लेखनीय है कि किसी भी विधानसभा सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही पहले स्थगित की जाती है।

जेलों में हिंसा पर जीरो टॉलरेंस: किसी भी घटना के लिए संबंधित सुपरिंटेंडेंट होंगे जिम्मेदार, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई – डॉ. रवजोत सिंह



चंडीगढ़, 1 जून:पंजाब सरकार ने राज्य की जेलों में सुरक्षा, अनुशासन और सुधारात्मक माहौल को और मजबूत बनाने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। जेल मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में किसी भी जेल में हिंसक घटना, सुरक्षा में चूक या प्रशासनिक लापरवाही सामने आने पर संबंधित जेल सुपरिंटेंडेंट और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी तथा उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

चंडीगढ़, 1 जून:पंजाब सरकार ने राज्य की जेलों में सुरक्षा, अनुशासन और सुधारात्मक माहौल को और मजबूत बनाने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। जेल मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में किसी भी जेल में हिंसक घटना, सुरक्षा में चूक या प्रशासनिक लापरवाही सामने आने पर संबंधित जेल सुपरिंटेंडेंट और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी तथा उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जेल मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से अपनी कार्यप्रणाली और कार्यक्षमता का मूल्यांकन करें, कमियों और कमजोरियों की पहचान कर उन्हें दूर करें तथा उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार और सक्षम अधिकारी वही है जो सीमित संसाधनों में भी अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी, निष्ठा और पेशेवर दृष्टि से निभाए।

बैठक में जेल सुरक्षा व्यवस्था, कैदियों की भलाई, प्रशासनिक कार्यप्रणाली और विभागीय दक्षता को बेहतर बनाने पर विशेष चर्चा की गई। डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि आधुनिक जेल प्रबंधन का उद्देश्य केवल कैदियों को हिरासत में रखना नहीं है, बल्कि उनके व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव लाकर उन्हें समाज की मुख्यधारा में वापस शामिल करना भी है। इसलिए जेलों में सुधार, पुनर्वास और कौशल विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कैदियों के लिए शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं और मनोवैज्ञानिक परामर्श जैसी सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाए ताकि वे सजा पूरी होने के बाद एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में समाज में पुनः स्थापित हो सकें।

बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों ने जेलों में चल रहे विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रमों, स्वास्थ्य सुविधाओं, भोजन प्रबंधन, स्टाफ भर्ती, बुनियादी ढांचे के विकास तथा कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत प्रस्तुति दी। जेल मंत्री ने इन सभी क्षेत्रों में निरंतर सुधार और पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया।

इस अवसर पर जेल विभाग के सचिव मोहम्मद तईब, एडीजीपी जेल आर.के. जायसवाल, पंजाब की विभिन्न जेलों के सुपरिंटेंडेंट तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

पंजाब विधानसभा चुनावों की तैयारी तेज: मान सरकार ने चुनाव विभाग को किया मजबूत, सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी

चंडीगढ़, 1 जून:मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए चुनाव विभाग की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने चुनाव विभाग के सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिससे लंबे समय से चली आ रही प्रशासनिक बाधाएं दूर होंगी और मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) सहित चुनाव संबंधी कार्यों को सुचारू ढंग से संचालित किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिए गए इस फैसले के तहत चुनाव कानूनगो से चुनाव तहसीलदार के पद पर पदोन्नति के लिए आवश्यक अनुभव की अवधि 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दी गई है। सरकार का मानना है कि इस कदम से विभाग में रिक्त पड़े महत्वपूर्ण पदों को शीघ्र भरा जा सकेगा और चुनावी व्यवस्थाओं को समय रहते मजबूत किया जा सकेगा।



सकेगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, चुनाव तहसीलदारों के सात पद लंबे समय से खाली पड़े हुए हैं। वर्तमान नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिए 15 वर्ष का अनुभव अनिवार्य था, जिसके चलते विभाग में कार्यरत कोई भी चुनाव कानूनगो इस पद के लिए पात्र नहीं था। इससे चुनावी कार्यों के संचालन में कठिनाइयां आ रही थीं। अनुभव सीमा को 12 वर्ष किए जाने से योग्य अधिकारियों को पदोन्नति का अवसर मिलेगा और

विभाग को आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध हो सकेगा।

सरकार का मानना है कि मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण और आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के दौरान चुनाव तहसीलदारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में रिक्त पदों को भरना समय की मांग थी। इस निर्णय से चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।

बैठक के दौरान मंत्रिमंडल ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में जल संसाधन विभाग की वर्ष 2025-26 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट को भी मंजूरी प्रदान की। इस रिपोर्ट में विभाग द्वारा वर्ष भर किए गए प्रशासनिक कार्यों, योजनाओं, उपलब्धियों और विकास गतिविधियों का विस्तृत विवरण शामिल है।

मुख्यमंत्री सेहत योजना बनी
जीवनदायिनी: गुरप्रीत कौर को
मिला नया जीवन



चंडीगढ़, 1 जून:पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना (एमएमएसवाई) राज्य के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक 45 लाख से अधिक लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं और हजारों परिवार महंगे इलाज का लाभ उठा चुके हैं।

बठिंडा की 37 वर्षीय गुरप्रीत कौर इसका जीवंत उदाहरण हैं। उनके हृदय में जन्मजात 22 मिमी का बड़ा छेद (एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट) पाया गया, जिससे गंभीर स्वास्थ्य खतरा उत्पन्न हो गया था। इलाज का खर्च परिवार के लिए बड़ी चिंता बन गया था, लेकिन मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत लगभग एक लाख रुपये की लागत वाला उपचार निःशुल्क संभव हो सका।

5 मई 2026 को एम्स बठिंडा में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक हृदय की सर्जरी कर दोष को बंद किया। ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा और गुरप्रीत अब स्वस्थ जीवन की ओर लौट रही हैं।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि कोई भी परिवार आर्थिक तंगी के कारण गुणवत्तापूर्ण इलाज से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि अब तक योजना के तहत 1.75 लाख से अधिक मरीजों को 3.43 लाख उपचार प्रदान किए जा चुके हैं, जबकि राज्य सरकार इस पर 581.90 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। यह योजना पंजाब में स्वास्थ्य सुरक्षा की मजबूत ढाल बनकर उभरी है।

जातिसूचक टिप्पणी मामले में
रवनीत बिट्टू को एससी आयोग
का समन

चंडीगढ़, 1 जून: पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने केन्द्रीय रेल राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को कथित जातिसूचक शब्दों के प्रयोग के मामले में 4 जून 2026 को आयोग के समक्ष पेश होने के लिए तलब किया है। आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गद्दी ने बताया कि धूरी दौरे के दौरान बिट्टू की कथित टिप्पणी का मामला सोशल मीडिया के जरिए संज्ञान में आया था। इस संबंध में एसएसपी संगरूर से रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से आयोग ने असहमति जताते हुए बिट्टू को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है।

SquareNet
Innovation & Excellence

Zoho Mail

Google Workspace

Microsoft 365

Microsoft Solutions Partner

Google Cloud Partner

aws partner network

Are you looking for a reliable EMAIL SERVICE PROVIDER?

Choose the best suitable plan for your business from SquareNet

Secure & Reliable

Professional Email

Cloud Integration

24/7 Expert Support

Scalable for Every Business

Empower Your Business with Secure, Professional & Scalable Email Solutions

SQUARENET INDIA PRIVATE LIMITED
C-6, Sebiz Square, IT Park, Sector 67,
Mohali 160062, Punjab India

www.squarenetindia.com

mail@squarenetsolutions.com

+91-904-101-2541
[PRI LINE]

Visit Us: www.azadvaani.com

For Enquiry Call: +91-90414-88440

‘ब्राइट माइंडज़ पंजाब 2026’ की शानदार शुरुआत: : 600 से अधिक मेधावी छात्रों का सम्मान



चंडीगढ़, 1 जून:पंजाब सरकार ने राज्य में शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने और मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से ‘ब्राइट माइंडज़ पंजाब 2026’ कार्यक्रम की शुरुआत रूपनगर जिले से की है। श्री आनंदपुर साहिब स्थित विरासत-ए-खालसा में आयोजित उद्घाटन समारोह में शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस और आम आदमी पार्टी के पंजाब मामलों के प्रभारी मनीष सिसोदिया ने भाग लिया तथा 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 600 से अधिक विद्यार्थियों को सम्मानित किया।

इस अवसर पर विद्यार्थियों को अवीगॅट सर्टिफिकेट प्रदान किए गए और उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों की सराहना की गई। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस ने घोषणा की कि यह कार्यक्रम अब पंजाब के सभी जिलों में आयोजित किया जाएगा ताकि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिल सके और उन्हें शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए अपने सुझाव देने का अवसर भी प्राप्त हो। एआई भविष्य में रोजगार और नवाचार के नए अवसर पैदा करेगा, इसलिए पंजाब के विद्यार्थियों को इस क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में यह कदम उठाया गया है।

हरित पंजाब की ओर बड़ा कदम: राज्यभर में लगाए जाएंगे 1.50 करोड़ पौधे



चंडीगढ़, 1 जून:पंजाब को स्वच्छ, हरित और पर्यावरणीय रूप से समृद्ध बनाने की दिशा में वन एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग ने एक महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया है। विभाग ने राज्य के सभी 23 जिलों में 6.50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके तहत पूरे पंजाब में लगभग 1.50 करोड़ पौधों का रोपण किया जाएगा। यह विशेष अभियान श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित होगा।

वन एवं वन्यजीव संरक्षण मंत्री लाल चंद कटारूचक ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान मंडलीय वन अधिकारियों (डीएफओ) को निर्देश दिए कि वे अपने अपने जिलों के उपायुक्तों के साथ समन्वय स्थापित कर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देने के लिए समाज के विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों और संस्थाओं को भी इस अभियान से जोड़ा जाए।

मंत्री ने राज्य राजमार्गों के दोनों ओर हरित पट्टी विकसित करने पर विशेष जोर देते हुए निर्देश दिए कि बड़े जिलों में दो और छोटे जिलों में एक उपयुक्त स्थान की पहचान की जाए, जहां 500 मीटर की दूरी तक पोधारोपण किया जा सके। उन्होंने सभी डीएफओ को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर चिन्हित स्थलों का विवरण 10 जून तक मुख्यालय को भेजने के लिए कहा।



Advertisement



N M CONSTRUCTION

Excellence in every structure

#219 GF Maa Shimla Complex, Landran Road, Kharar, SAS Nagar, 140301, Punjab

Email: nmconstruction5151@gmail.com | Phone: +91-6009610096, 9872766841

पंजाब में जीएसटी संग्रह ने भरी नई उड़ान: मई में 14.59% वृद्धि, 85.4 करोड़ के फर्जी बिलिंग रैकेट का भंडाफोड़



चंडीगढ़, 1 जून 2026:पंजाब ने वित्तीय मजबूती और कर संग्रह के क्षेत्र में एक और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। वित्त, आबकारी एवं कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने सोमवार को बताया कि मई 2026 के दौरान राज्य के सकल जीएसटी संग्रह में 14.59 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई है। मई 2026 में पंजाब का कुल जीएसटी संग्रह 2,400.52 करोड़ रुपये रहा, जबकि मई 2025 में यह आंकड़ा 2,094.81 करोड़ रुपये था। इस प्रकार राज्य ने एक वर्ष में 305.71 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राजस्व वृद्धि हासिल की है।

वित्त मंत्री ने कहा कि यह उल्लेखनीय बढ़ोतरी राज्य में मजबूत आर्थिक गतिविधियों, करदाताओं द्वारा बेहतर अनुपालन तथा आबकारी एवं कराधान विभाग की प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई का परिणाम है। उन्होंने कहा

कि पंजाब का प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर की तुलना में कहीं अधिक बेहतर रहा है। जहाँ देशभर में सकल जीएसटी राजस्व वृद्धि लगभग 3.2 प्रतिशत रही, वहीं पंजाब ने 14.59 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर अपनी मजबूत राजस्व व्यवस्था और कुशल कर प्रशासन का परिचय दिया है।

उन्होंने बताया कि राज्य की नकद कर संग्रह वृद्धि 6.57 प्रतिशत रही, जबकि सकल जीएसटी संग्रह में वृद्धि 14.59 प्रतिशत तक पहुंची। यह राज्य के बढ़ते राजस्व आधार, बेहतर कर अनुपालन और प्रभावी प्रशासनिक उपायों को दर्शाता है।

प्रवर्तन कार्रवाइयों का विवरण देते हुए हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पंजाब भर में कार्यरत स्टेट इंटेलिजेंस एंड प्रिवेंटिव यूनिट्स (एसआईपीयू) ने मई

2026 के दौरान 182.69 करोड़ रुपये के जुर्माने लगाए तथा 178.76 करोड़ रुपये की वसूली की। उन्होंने कहा कि यह सफलता डेटा एनालिटिक्स, खुफिया जानकारी आधारित जांच, लक्षित सत्यापन अभियानों और राज्यभर में चलाए गए समन्वित फील्ड ऑपरेशनों के कारण संभव हुई है।

कर चोरी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए पंजाब कराधान विभाग ने मई 2026 के दौरान 85.4 करोड़ रुपये के फर्जी बिलिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया। इस मामले में लुधियाना स्थित एक कंपनी के निदेशक को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर फर्जी लेन-देन के माध्यम से 15.56 करोड़ रुपये का अवैध इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) हासिल करने का आरोप है।

पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था होगी और मजबूत: डीजीपी गौरव यादव ने बढ़ाने के निर्देश दिए नाके, गश्त और वाहन जांच



चंडीगढ़, 1 जून:मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुरूप पंजाब में सुरक्षित और भयमुक्त गहलौल सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने का फैसला किया है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने सोमवार को सभी जिला और कमिश्नरेट पुलिस अधिकारियों को पुलिस की मेदान में मौजूदगी बढ़ाने, रणनीतिक नाके लगाने, मोबाइल गश्त तेज करने और व्यापक वाहन जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

डीजीपी गौरव यादव ने यह निर्देश राज्य स्तरीय कानून-व्यवस्था समीक्षा बैठक के दौरान दिए, जिसमें विशेष डीजीपी, अतिरिक्त डीजीपी, आईजीपी, डीआईजी, सभी पुलिस कमिश्नर और जिला पुलिस प्रमुख वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करना, अपराध नियंत्रण को और प्रभावी बनाना तथा

विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस की सक्रिय मौजूदगी बढ़ाना था।

डीजीपी ने कहा कि सभी पुलिस कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में नाकों की संख्या बढ़ाने और अधिक से अधिक वाहनों की गहन जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मोबाइल गश्त को भी तेज किया जाएगा ताकि असामाजिक और आपराधिक तत्वों पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके तथा पूरे राज्य में मजबूत सुरक्षा कवच स्थापित किया जा सके।

उन्होंने जिला पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिए कि अधिकतम पुलिस बल को मेदान में तैनात किया जाए ताकि आम लोगों में सुरक्षा और विश्वास की भावना मजबूत हो सके। डीजीपी ने कहा कि पुलिस की सक्रिय मौजूदगी अपराधों की रोकथाम और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

बैठक के दौरान पंजाब सरकार के दो प्रमुख अभियानों ‘युद्ध नशां विरुद्ध’ और ‘गैंगस्टरों से वार’ की प्रगति की भी विस्तृत समीक्षा की गई। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि पंजाब पुलिस अब नशा तस्करी के वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करने पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके तहत अवैध हवाला ऑपरेटर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां उन लोगों की पहचान कर रही हैं जो मध्य-पूर्व के देशों के माध्यम से अवैध धन पाकिस्तान तक पहुंचाने और नशा कारोबार को वित्तीय सहायता देने का काम कर रहे हैं। ऐसे हवाला नेटवर्कों को पूरी तरह खत्म किया जाएगा और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

जनता के साथ बेहतर तालमेल और विश्वास बढ़ाने पर जोर देते हुए डीजीपी ने सभी पुलिस अधिकारियों को लोगों के साथ संवाद बढ़ाने के निर्देश दिए।

आशीर्वाद योजना के तहत 1241 परिवारों को 6.33 करोड़ रुपये की सहायता जारी



चंडीगढ़, 1 जून:पंजाब सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से आशीर्वाद योजना के तहत 1241 पात्र लाभार्थियों के लिए 6.33 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की है। यह सहायता पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के परिवारों को प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी बेटियों के विवाह के समय आर्थिक बोझ को कम करने में मदद मिलेगी।

सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी दिशा में आशीर्वाद योजना के तहत विभिन्न जिलों से प्राप्त पात्र आवेदनों को मंजूरी देकर सहायता राशि जारी की गई है।

उन्होंने बताया कि अमृतसर, बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, श्री फतेहगढ़ साहिब, जलंधर, कपूरथला, मानसा, पटियाला, पठानकोट, एस.ए.एस. नगर (मोहाली), एस.बी.एस. नगर और मालेरकोटला सहित 13 जिलों के कुल 1241 पात्र लाभार्थियों के आवेदन आशीर्वाद पोर्टल पर प्राप्त हुए थे। इन सभी लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए 6.33 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

विरासत-ए-खालसा समेत प्रमुख संस्थानों पर लगेंगे सोलर प्लांट



चंडीगढ़, 1 जून:पंजाब सरकार ने स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए विरासत-ए-खालसा, श्री आनंदपुर साहिब, भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल अमृतसर और नाइबे कपूरथला सहित प्रमुख संस्थानों पर 2 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का फैसला किया है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि विरासत-ए-खालसा में 500 किलोवाट, भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल में 400 किलोवाट और नाइबे कपूरथला में 300 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि राज्य के 661 सरकारी भवनों पर 18.6 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के कार्यदिश भी जारी कर दिए गए हैं। अब तक 34 सरकारी भवनों पर 1.413 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। मंत्री ने इन प्रमुख परियोजनाओं को अगस्त 2026 के मध्य तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोशनी की सुविधा बढ़ाने के लिए अगले छह महीनों में 3 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाने का लक्ष्य भी तय किया गया है। अब तक पंजाब के 5,835 गांवों में 1.19 लाख से अधिक सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई जा चुकी हैं। सरकार का मानना है कि इन पहलों से बिजली खर्च में करोड़ों रुपये की बचत होगी।

herbegy™

Think pure think herbal

PREMIUM SPICES RANGE

Pure Spice. Rich Flavour.



PURE | AROMATIC | PREMIUM QUALITY

Advertisement

For Dealer Inquiry Contact:

727-515-0015